

एकता केसरी

EKTA KESARI

Issue: 2 • Volume: 8 • Hindi Weekly • Mumbai, Friday 21 to 27 March 2025 • Price 5/- • Page 8

गुजरात के नियम अब महाराष्ट्र में होंगे लागू सरकारी कर्मचारियों पर कसेगी नकेल, सीएम ने किया बड़ा ऐलान

मुंबई: सोशल मीडिया पर सरकारी अधिकारियों की सक्रियता पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। इस पर अब महायुक्ति सरकार एक्शन लेने जा रही है। सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सोशल मीडिया पर बढ़ रही सक्रियता पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार साल 1979 के सेवा शर्तों के नियमों में संशोधन करेगी और नये नियम बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि अधिकारियों – कर्मचारियों के आचरण के संबंध में उपयुक्त नियम बनाए जाएंगे और इन नियमों को सेवा-शर्तों का हिस्सा बनाया जाएगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस संबंध में जल्द जीआर जारी किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अनियंत्रित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधान



परिषद में विधायक डॉ. परिणय फुके ने ध्यानाकर्षण सूचना के तहत सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सोशल मीडिया पर बढ़ रही सक्रियता को लेकर सवाल उठाए थे। गुजरात और जम्मू-कश्मीर में बने नियम इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 1979 में सेवा नियम बनाए गए थे। उस समय सोशल मीडिया नहीं था। कई जगह

सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ पोस्ट करते हैं। वे अपने कर्तव्य का महिमामंडन करते प्रतीत होते हैं, इसलिए कुछ नियम आवश्यक हैं। सरकार जनता से जुड़ने और नागरिकों की सहभागिता के लिए सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ाने की आशा करती है। इस बारे में अध्ययन करने पर पता चला है कि गुजरात **शेष पृष्ठ २ पर**

सावधान! नागपुर हिंसा पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों की हुई पहचान, साइबर सेल ने लिया बड़ा एक्शन



नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर में भड़की हिंसा में पुलिस को बुधवार को बड़ी सफलता मिली। नागपुर हिंसा के कथित मास्टरमाइंड फहीम खान को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जांच में बहुत-सी चीजों का खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि नागपुर में पूरा बवाल फहीम खान के भड़काए जाने पर ही किया गया था। फहीम खान के कहने पर भीड़ जमा की गई। इसके लिए सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया गया।

इस हिंसा के चलते पुलिस ने दोषियों पर भी पैनी नजर रखी है। नागपुर हिंसा के चलते किन लोगों ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए हैं, उन अकाउंट्स पर पुलिस ने एक्शन लिया है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने **शेष पृष्ठ २ पर**

मुंबई: बांद्रा में छापेमारी के बाद सोबो का प्रमुख गांजा आपूर्तिकर्ता गिरफ्तार

बांद्रा क्राइम ब्रांच की यूनिट IX ने दक्षिण मुंबई में गांजे के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता को गिरफ्तार किया है, छापेमारी के बाद बांद्रा पश्चिम ट्रॉजिट कैप में 10x10 फुट के कमरे से लगभग 71 लाख रुपये मूल्य की लगभग 286 किलोग्राम साइकोएक्टिव दवा जब्त की है। आरोपी की पहचान तारदेव के तुलसीवाड़ी निवासी 36 वर्षीय इमरान कमलुद्दीन अंसारी के रूप में हुई है, जिसे कई चोरी और डकैती के मामलों में गिरफ्तार किया गया है।



हालाँकि, यह पहली बार है जब वह नशीली दवाओं से संबंधित अपराध में पकड़ा गया है। बांद्रा रिक्लेमेशन

के ट्रॉजिट कैप में स्थित घर, जिस पर 18 मार्च को छापे मारा गया था पुलिस के मुताबिक, झारखंड से

शहर में ड्रग्स पहुंचाने वाले आरोपी ने पिछले महीने अपने जीजा के नाम का इस्तेमाल करते हुए बांद्रा रिक्लेमेशन में छोटा कमरा किराए पर लिया था। अपराध शाखा के एक अधिकारी ने कहा, रहम गुप्त सूचना मिली थी कि अंसारी अपने आवास पर गांजा जमा कर रहा है। गांजे की तेज गंध पड़ोसी घरों में भी फैलने लगी थी। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, यूनिट IX ने 18 मार्च को घर पर छापे मारा और आरोपी को प्रतिबंधित सामग्री **शेष पृष्ठ २ पर**

दिशा सालियान सुसाइड केस: क्या होंगे आदित्य ठाकरे गिरफ्तार! पिता की बॉम्बे HC में याचिका, कभी जांच से थे खुश

मुंबई: एक बड़ी खबर के अनुसार अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने दिशा की मौत की नए सिरे से जांच की मांग करते हुए बीते बुधवार को उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं इस याचिका में शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज करने और जांच CBI को सौंपने का आग्रह भी किया

गया है। उनका आरोप है कि दिशा के साथ सामुहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। जानकारी दें कि, BJP नेता नितेश राणे ने ही आज से तीन साल पहले दिशा से गैंगरेप के बाद उनकी हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि तब दिशा के माता-पिता ने बेटी को बदनाम करने की साजिश कहते हुए



उल्टा नितेश पर ही केस दर्ज कराया था। वहीं अब दिशा के पिता का कहना है कि उन्हें नजरबंद करके पुलिस के पेश सबूतों को सच मानने के लिए मजबूर किया गया था। इसके साथ ही अपनी इस याचिका में उन्होंने सूरज पांचोली, डिनो मोर्या और मुंबई पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दिशा सालियान के पिता सतीश

सालियान ने इस बाबत बुधवार को कहा कि उन्होंने जून 2020 में रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई अपनी बेटी की मौत की नये सिरे से जांच कराने के लिए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सतीश ने कहा कि याचिका में उच्च न्यायालय से शिवसेना (उबाठा) नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो **शेष पृष्ठ २ पर**

संपादकीय

आक्रांता के महिमामंडन की बीमारी

हाल में महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की महानता का बखान करते हुए उसका गुणगान किया। विरोध के बाद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन उससे देश की राजनीति में उबाल आ गया और नागपुर में तो हिंसा भी हो गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। देश का आम जनमानस औरंगजेब को बर्बर ही मानता है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग उसे दयालु और महान शासक बताने में लगे रहते हैं। किसी शासक को महान या क्रूर बताने से पहले हमें उसके व्यक्तित्व, उसके शासनकाल में अपनाई गई नीतियों और उसने अपनी प्रजा से किस प्रकार व्यवहार किया आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। औरंगजेब का आकलन तथ्यों पर कम और सुनी-सुनाई बातों और धार्मिक पूर्वाग्रहों पर अधिक होता है। इस क्रम में कई बार उसके ही दरबारी की ओर से लिखी गई बातों की भी अनदेखी कर दी जाती है। किसी राजा को महान तभी कहा गया, जब उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य किया, जिसके शासन में प्रजा पर करों का बोझ कम से कम रहा हो और धार्मिक-भेदभाव न किया गया हो तथा साहित्य, कला, व्यापार, विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों में राज्य ने चहुंमुखी प्रगति की हो। कुछ तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने औरंगजेब की कट्टरता के कारण ही उसे आदर्श समझकर उसका महिमामंडन किया और 'जिंदा-पीर' की उपाधि दी। बाद के कुछ इतिहासकारों ने भी इसी आधार पर उसका महिमामंडन किया, जो तथ्यों से मेल नहीं खाता। क्या उसे सिर्फ इसलिए महान कहना चाहिए कि उसने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भू-भाग पर राज किया? बड़ा राज्य शासक की महानता का प्रमाण नहीं है। औरंगजेब ने जिस प्रकार गद्दी प्राप्त की, उस पर ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तब उत्तराधिकार अन्य दावेदारों या शासक का कत्ल करके ही हासिल किया जाता था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां के जीवित रहते ही गद्दी पाने के लिए अपने भाइयों से युद्ध लड़ा। उसने अपने भाई दारा शिकोह को यह झूठा आरोप लगाकर मारा कि उसने इस्लाम के विरुद्ध कार्य किया है। उसने दारा को निर्ममता से मारा और उसका सिर कलम कर पिता शाहजहां को तशरी में पेश किया। क्या इसे हद दर्जे की क्रूरता नहीं कहा जाएगा? उसने दारा के पुत्र सुलेमान और अपने भाई मुराद को भी धोखे से मरवाया। उसने अपने पिता शाहजहां को पानी के लिए तड़पाया और मरते दम तक कैदखाने में रखा। शाहजहां के जनाजे में भी शामिल नहीं हुआ। उसके डर से अन्य दरबारी भी जनाजे में शामिल न हो सके। शाहजहां को मामूली नौकरों और किन्नरों द्वारा दफनाया गया। जो यह साबित करना चाहते हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं को भी नौकरी दी, तो उन्हें यह जानना चाहिए कि इसके पीछे उसकी राजनीतिक मजबूरी थी, क्योंकि शिवाजी तथा उनके वंशजों को वश में करने के लिए वह उन सभी हिंदू सरदारों को अपनी सेना में भर्ती कर उन्हें जागीरें देता गया, जो उनके विरोधी थे। दो-तीन जागीरदारों को छोड़कर अन्य हिंदू जागीरदार औरंगजेब के दरबार में उच्च-पदों पर नहीं थे। औरंगजेब ने यही कोशिश की कि हिंदुओं को प्रशासन में कम से कम अवसर दिए जाएं। इसके लिए उसने राजस्व-विभाग में लगे हिंदुओं को नौकरियों से हटाने का कार्य किया, किंतु जब लगान वसूलने का कार्य संभव नहीं हो सका, तब उसने हिंदुओं को पुनः नियुक्तियां दीं। विद्रोह सभी शासकों के काल में होते रहे हैं, किंतु औरंगजेब के सनक भरे तौर-तरीकों के चलते उसके काल में विद्रोहों की झड़ी लग गई थी। उसके खिलाफ राजपूतों, जाटों, बुंदेलों, सिखों, शिथों एवं संन्यासियों के विद्रोह देखने को मिलते रहे। उसे सबसे अधिक नुकसान मराठों ने पहुंचाया। वह उनसे पार नहीं पा सका। अकबर ने गैर-मुस्लिमों से जिस जबरिया उगाही 'जजिया' पर रोक लगाई थी, औरंगजेब ने उसे फिर से शुरू किया।

अराजकता फैलाने की खुली धमकी, प्रस्तावित कानून के खिलाफ मोर्चा खोलना संविधान पर सीधा हमला

जब नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए आया था तो उसे लेकर जिस झूठ का सबसे अधिक सहारा लिया गया था, वह यह था कि इसके जरिये भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छीनने का काम किया जाएगा। इसी तरह तीन कृषि कानूनों के विरोध में यह झूठ जमकर फैलाया गया था कि इनका उद्देश्य किसानों की जमीन छीनकर उन्हें उद्योगपतियों को देना है। अब वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भी यह झूठ फैलाया जा रहा है कि इसके जरिये मुसलमानों की मस्जिदें, दरगाह, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। इस झूठ का सहारा रमजान के दिनों में भी लेने में संकोच नहीं किया जा रहा है। इस विधेयक के खिलाफ दिल्ली में जंतर-मंतर पर आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की ओर से आयोजित प्रदर्शन के दौरान इसी झूठ को कई बार दोहराया गया। इस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम सिविल राइट्स के चेयरमैन मोहम्मद अदीब की ओर से यहां तक कहा गया कि जगदंबिका पाल (वक्फ अधिनियम पर विचार करने वाली जेपीसी के अध्यक्ष) को खबर कर दें कि वह यह बिल पास करके दिखाएं, फिर देखना कि हम उनका क्या हथ्र करेंगे? उनकी ओर से जदयू, तेलुगु देसम जैसे दलों को भी देख लेने की धमकी दी गई। इसी आयोजन में यह भी कहा गया कि यदि जरूरत पड़ी तो हम



दिल्ली और यूपी बांडर बंद करने के लिए भी तैयार रहेंगे। शाहीन बाग जैसा धरना देने की भी धमकी दी गई। यह ध्यान रहे कि सीएए के खिलाफ धरने के दौरान शाहीन बाग में दिल्ली को यूपी से जोड़ने वाले एक प्रमुख रास्ते पर कब्जा कर लिया गया था। तब विपक्ष के छोटे-बड़े नेता शाहीन बाग पहुंचकर इस अराजक धरने को जायज ठहराते थे। हालांकि इस धरने से त्रस्त लोगों की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन उसके दुलमुल रवैये के चलते धरना जारी रहा और अंततः कई महीनों बाद वह तब खत्म हुआ, जब कोरोना के चलते लाकडाउन लगा और वहां मुट्ठी भर लोग ही बचे। कृषि कानून विरोधी आंदोलन के समय भी कथित किसान नेता करीब साल भर दिल्ली की सीमाओं पर राजमार्गों को इसलिए बाधित किए बैठे रहे थे, क्योंकि न तो सरकार ने जबरदस्ती रास्ते रोकने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई और न ही सुप्रीम कोर्ट ने। तब इसकी भी अनदेखी कर दी गई थी कि



ट्रैक्टर परेड निकालकर गणतंत्र दिवस मनाने के बहाने लाल किले पर कैसा उपद्रव किया गया था। जहां सीएए और कृषि कानूनों का विरोध उन पर संसद की मुहर लगने के बाद किया गया था, वहीं वक्फ अधिनियम का विरोध उसके संसद में पेश होने के पहले ही किया जा रहा है। एक तरह से संसद को कानून बनाने से ही रोकने की कोशिश की जा रही है और वह भी संविधान की दुहाई देते हुए। कहा जा रहा है कि वक्फ अधिनियम से छेड़छाड़ संविधान से छेड़छाड़ है। संविधान को धर्मग्रंथ जैसा भले बताया जाता हो, लेकिन वह धर्मग्रंथ नहीं होता और न होना चाहिए। उसमें संशोधन होते रहते हैं-ठीक वैसे ही जैसे, अतीत में वक्फ अधिनियम में भी होते रहे। वक्फ अधिनियम में संशोधन के विरोध में यह कुतर्क कुछ ज्यादा ही जोरदार ढंग से दिया जा रहा है कि चूंकि उसमें कोई खामी नहीं, इसलिए उसमें किसी तरह के परिवर्तन की जरूरत भी नहीं। यह कुतर्क तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल,

गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों से हैरान करने वाली उन खबरों के बाद भी किया जा रहा है, जिनके तहत यह उजागर हुआ कि वक्फ बोर्डों ने किस मनमाने तरीके से किसानों, मछुआरों, आम लोगों की जमीनों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। तमिलनाडु में तो 1500 साल पुराने यानी इस्लाम के उदय के पहले के एक मंदिर की जमीन को ही वक्फ संपत्ति बता दिया गया। वक्फ बोर्डों के पास रेलवे और सेना के बाद सबसे अधिक जमीन है, लेकिन उसकी हजारों संपत्तियों को लेकर विवाद है। इनमें से अनेक विवाद अदालतों में विचाराधीन हैं। इसके बाद भी मौजूदा वक्फ अधिनियम को सही ठहराया जा रहा है। यदि इस वक्फ अधिनियम में कहीं कोई विसंगति नहीं और वक्फ बोर्ड सचमुच नीर-क्षीर तरीके से संचालित हो रहे हैं तो फिर क्यों न अन्य समुदायों के लिए भी ऐसे ही बोर्ड बना दिए जाएं? शायद हिंदू समाज को ऐसे किसी बोर्ड की आवश्यकता सबसे अधिक है, क्योंकि उसके धार्मिक स्थलों की संपत्तियों पर कब्जा या फिर उनका दुरुपयोग होता रहता है। आखिर यह कहां का न्याय है कि एक समुदाय के धार्मिक स्थलों का नियमन-संचालन तो सरकारें करें, लेकिन अन्य समुदाय के धार्मिक स्थलों का संचालन उसके लोग खुद करें?

पृष्ठ 1 का शेष

दिशा सालियान सुसाइड केस

(सीबीआई) को सौंपने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। इधर दिशा के पिता की इस याचिका के बाद महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है। इस बाबत कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने कहा, 'आदित्य ठाकरे को विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच का सामना करना ही चाहिए।' हालांकि, शिवसेना (उबाठा) के प्रवक्ता ने आश्चर्य जताया कि चार साल बाद अचानक यह मामला सुर्खियों में क्यों आ गया। उन्होंने इसमें साजिश की आशंका जताई। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र अभी चल रहा है। सतीश सालियान के वकील नीलेश ओझा ने कहा कि वे अभी भी याचिका दायर करने की प्रक्रिया में हैं और आज हाई कोर्ट के रजिस्ट्री विभाग में इस पर नंबर दर्ज कराएंगे। बताते चलें कि, दिशा सालियान की मौत आठ जून 2020 को उपनगरीय मलाड में एक आवासीय इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई थी। इसके बाद शहर की पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया था। वहीं उस समय दिशा के पिता ने इस जांच को संतोषजनक भी करार दिया था।

गुजरात के नियम अब महाराष्ट्र

और जम्मू-कश्मीर सरकारों ने इसके लिए अच्छे नियम बनाए हैं। विधायक फुके ने उठाया सवाल इससे पहले फुके ने कहा कि सरकारी अधिकारी-कर्मचारी रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से यह छवि बनाई गई है कि जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक या पुलिस इंस्पेक्टर ही पूरे क्षेत्र के सभी मामलों की देखरेख करते हैं। वे ही राज्य को चलाते हैं। अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। इसके लिए सख्त नियम बनाए जाने चाहिए। महाराष्ट्र सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत पिछले 3 वर्षों में कितने कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है?

मुंबई: बांद्रा में छापेमारी के बाद सोबो

के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। अधिकारी ने कहा, रूपा घर गांजे की बड़ी बोरियों से भरा हुआ था। अधिकारियों ने सभी सामग्री को हटा दिया और ज्वट कर लिया। रजांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि अंसारी की मां को पहले तुलसीवाड़ी में गांजा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अंसारी के पड़ोसियों में से एक ने एकता केसरी को बताया, जिन्होंने पड़ोसी के घर से तेज गंध आती देखी। पहले तो हमें लगा कि वह गुटखा या ऐसा ही कुछ मिला रहा है, लेकिन दिन-ब-दिन दुर्गंध बढ़ती गई। हमने उसे अक्सर घर में छोटे बैग ले जाते हुए भी देखा। बैग रखने के बाद वह परिसर में ताला लगा देता था। वह 5000 रुपये प्रति माह की बेहद सस्ती दर पर कमरा किराए पर लेने में कामयाब रहे।

सावधान! नागपुर हिंसा पर भड़काऊ

एक्शन लेते हुए कुछ लोगों की पहचान कर ली है। साइबर सेल पुलिस ने अब इस मामले में भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सभी को नोटिस भेजा है। साइबर सेल ने लिया एक्शन महाराष्ट्र साइबर सेल का कहना है, 'हमने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले कुछ लोगों की पहचान की है। उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है।' बताया जा रहा है कि उसके कहने पर सैकड़ों लोगों की भीड़ थाने पर जमा हुई थी, जिसके बाद पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया और दर्जनों वाहनों को आग लगा दी गई। वहीं, एक सोशल मीडिया अकाउंट से भी फहीम खान को लेकर नए खुलासे हुए हैं। जांच के दौरान नागपुर पुलिस को सोशल मीडिया अकाउंट से कई सबूत मिले हैं। इसमें घटना के दिन के कई वीडियो और धमकी भरे सोशल मीडिया पर पोस्ट मिले। इस पेज पर 17 मार्च को हुई आगजनी और दंगों के वीडियो शेयर किए गए हैं। साथ ही एक पोस्ट में औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात करने वालों के हाथ काटने की धमकी भी दी गई थी।

मुंबई फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस घोटाला

ऑडिट में फर्जी टेस्ट के जरिए 76,000 लाइसेंस जारी किए जाने का खुलासा होने के बाद 2 आरटीओ अधिकारी निलंबित,

मुंबई पश्चिम क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ), अंधेरी के दो अधिकारियों को फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस घोटाले के सिलसिले में हाल ही में निलंबित कर दिया गया है, जहां 2023-24 में अमान्य वाहनों पर संदिग्ध ड्राइविंग परीक्षण किए गए थे। निलंबित अधिकारियों, सहायक आरटीओ रावसाहेब रागडे और मोटर वाहन निरीक्षक उमेश देवरे को परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा की गई जांच के बाद निलंबित कर दिया गया। 10 मार्च के निलंबन आदेश के अनुसार, महाराष्ट्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा), नागपुर ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मुंबई पश्चिम आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में

अनियमितताओं को चिह्नित किया। महाराष्ट्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा-II) द्वारा किए गए ऑडिट के बाद यह कार्रवाई की गई, जिसमें पता चला कि एजेंटों और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से 'अनधिकृत' वाहनों पर किए गए 'फर्जी' ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर 76,000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस कैसे जारी किए गए। मुंबई आरटीओ ने तुरंत एक विवेकपूर्ण जांच शुरू की, जिसमें एक लाख से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस, उनके ड्राइविंग टेस्ट, दस्तावेज और उनकी देखरेख करने वाले अधिकारियों की जांच की गई। सारथी के ऑनलाइन डेटा के माध्यम से 1.04 लाख ड्राइविंग लाइसेंसों की जांच के दौरान चौकाने वाले विवरण सामने



आए, जो आवेदकों के लिए अनिवार्य ड्राइविंग टेस्ट आयोजित करने के बाद डीएल आवेदनों को संसाधित करता है। ऑडिट ने एक चौकाने वाला तथ्य उजागर किया: 2023-24 के लिए स्कैन किए गए 1.04 लाख लाइसेंसों में से, चौका देने वाला 76,354 डीएल-लगभग 75 प्रतिशत-अमान्य वाहनों पर



किए गए 'संदिग्ध' ड्राइविंग परीक्षणों पर आधारित थे। ठाणे स्थित सामाजिक कार्यकर्ता बीनू वर्गीस ने सीएजी जांच के बारे में आरटीओ को सूचित करने के बाद, अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इस मुद्दे के सड़कों पर हजारों ड्राइवरों के संदिग्ध ड्राइविंग कौशल के संबंध में

दूरगामी निहितार्थ थे। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल चार वाहनों-जिसमें दो दोपहिया वाहन और दो कारें शामिल हैं-का उपयोग विभिन्न वाहन श्रेणियों, जैसे स्कूटर से लेकर भारी-भरकम क्रेन तक के लिए ड्राइविंग टेस्ट आयोजित करने के लिए बार-बार किया गया, जिससे 76,354 संदिग्ध ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। इनमें से 41,093 ड्राइविंग लाइसेंस दो दोपहिया वाहनों का उपयोग करके जारी किए गए थे, जबकि अन्य 35,261 डीएल दो चार पहिया वाहनों का उपयोग करके जारी किए गए थे, जो संभावित कदाचार का संकेत देते हैं। इसके परिणामस्वरूप अंततः रागडे और देवरे को निलंबित कर दिया गया। ऑडिट की रिपोर्ट में इस बात

पर प्रकाश डाला गया कि हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के लिए लाइसेंस जारी किए गए, लेकिन ड्राइविंग टेस्ट दोपहिया वाहनों (मोटरसाइकिल) पर किए गए। यह मामला जून 2024 में महाराष्ट्र विधानमंडल में उठाया गया, जहाँ सरकार ने विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) को पूरी जाँच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आरटीओ की खिंचाई करते हुए ऑडिटर ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट आयोजित करने के लिए दस्तावेज तैयार करते समय न तो उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया और न ही अधिकृत आरटीओ निरीक्षकों द्वारा वाहन के विवरण का सत्यापन किया गया।

20 साल बाद, हाईकोर्ट ने नवी मुंबई में होटल निर्माण का रास्ता साफ किया

मुंबई: दो दशकों की देरी के बाद, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार को नवी मुंबई के सीबीडी-बेलापुर रोड, सेक्टर-15 में एक होटल के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। 2006 में सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड (CIDCO) द्वारा निविदा दी गई यह परियोजना प्रस्तावित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास न होने के कारण रुकी हुई थी। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ मुंबई स्थित पीवीपी स्टार होटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी,

जिसमें अतिरिक्त लीज प्रीमियम की मांग करने वाले CIDCO के कारण बताओ नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी। होटल व्यवसायी ने तर्क दिया कि मांग मनमानी थी, क्योंकि उन्हें अन्य लाइसेंसधारियों के समान लाभ नहीं दिए गए थे। होटल व्यवसायी के अनुसार, CIDCO ने दिसंबर 2006 में नवी मुंबई में एक होटल के निर्माण के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए थे, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और जल परिवहन सुविधाओं सहित आगामी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के साथ क्षेत्र को 'भविष्य के शहर' के रूप में बढ़ावा दिया गया था। होटल

व्यवसायी को 82 करोड़ का लीज प्रीमियम चुकाने के बाद प्लॉट आवंटित किया गया था, जिसमें समझौते के अनुसार निर्माण 12 महीने के भीतर शुरू होना था और पाँच साल के भीतर पूरा होना था। हालाँकि, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को एक प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजना के रूप में प्रचारित किया गया था जो होटल की मांग को बढ़ाएगा-कभी नहीं बनाया गया। इसके कारण, होटल व्यवसायी ने अतिरिक्त वित्तीय बोझ के बिना परियोजना को पूरा करने के लिए बार-बार विस्तार की मांग की। इन अनुरोधों के बावजूद, CIDCO ने

अप्रैल 2018 में पट्टे को समाप्त कर दिया, भूखंड पर कब्जा कर लिया और 12 करोड़ के अतिरिक्त पट्टे प्रीमियम की मांग की। होटल व्यवसायी ने तर्क दिया कि अन्य लाइसेंसधारियों को ऐसे वित्तीय दंड के बिना पट्टे का विस्तार दिया गया था, जिससे CIDCO की मांग अनुचित हो गई। जबकि अदालत ने स्वीकार किया कि पट्टे को समाप्त करना CIDCO के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होगा, इसने फैसला सुनाया कि होटल व्यवसायी अभी भी परियोजना में देरी के लिए अतिरिक्त पट्टे प्रीमियम का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार था।

7 दिन डिजिटल कस्टडी में रहोगी या 3 महीने थाने में... नकली सीबीआई के डर से मुंबई की महिला ने गंवा दिए 34 लाख

मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई में एक महिला के साथ बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ है। अंधेरी की रहने वाली 49 साल की इस महिला से 33.5 लाख रुपये ठग लिए गए। ठगों ने खुद को पुलिस और सीबीआई अफसर बताया। महिला पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया। झूठे अफसरों ने महिला को दो विकल्प दिए। या तो तीन महीने पुलिस हिरासत में रहो, या फिर जांच पूरी होने तक सात दिन के लिए डिजिटल हिरासत में रहो। महिला ने डिजिटल हिरासत का विकल्प चुना और अपनी सारी जमा पूंजी गंवा बैठी। पुलिस का कहना है कि मुंबई में डिजिटल हिरासत के नाम पर ठगी का यह पहला मामला हो सकता है। यह धोखाधड़ी 2 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच हुई। 25 फरवरी को इस मामले में केस दर्ज किया गया। महिला ने बताया कि उसे सबसे पहले TRAI से होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति का फोन आया। उसने कहा कि आपका मोबाइल नंबर दो घंटे में बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि आपके नंबर से कई लोगों को धमकी और फ्रॉड मैसेज भेजे जा रहे हैं। महिला ने इन आरोपों से इनकार किया। फिर एक दूसरा फोन आया। इस कॉलर ने बताया कि दिल्ली में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उसने कहा कि आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके गैरकानूनी गतिविधियाँ की जा रही हैं। आपके नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कई बैंक खाते खोले गए हैं।

'बीजेपी महाराष्ट्र को अगला मणिपुर बनाना चाहती है': आदित्य ठाकरे ने नागपुर हिंसा पर देवेंद्र फडनवीस सरकार पर हमला बोला

शिव सेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को मध्य नागपुर में सोमवार देर रात हुई हिंसक झड़पों को लेकर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए, आदित्य ने आरोप लगाया, 'मुझे लगता है कि बीजेपी महाराष्ट्र को अगला मणिपुर बनाना चाहती है... जब नागपुर में हिंसा फैल रही थी तो सीएमओ की ओर से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई?' सोमवार की रात, एक्स पर एक पोस्ट में, आदित्य ने इस घटना

पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पहले की तरह चरमरा गई है। सीएम और गृह मंत्री का गृह शहर नागपुर इसका सामना कर रहा है।' कल शाम की घटना ने राज्य में राजनीतिक हंगामा मचा दिया है, क्योंकि विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर भाजपा शासित राज्य सरकार पर हमला किया है। बीजेपी महाराष्ट्र को गुजरात बनाने की कोशिश कर रही है: कांग्रेसपूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी और कांग्रेस



सांसद प्रणीति शिंदे ने नागपुर हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, 'वे (बीजेपी का जिक्र करते हुए) महाराष्ट्र को

गुजरात में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जब से वे सत्ता में आए हैं, उन्होंने बार-बार समाज में धर्म को बढ़ावा देने के लिए विभाजन पैदा

करने की कोशिश की है...' उन्होंने गुजरात में ऐसा किया... सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पीएम (मोदी) खुद अपनी यात्राओं के दौरान उत्तेजक भाषण देते हैं... महाराष्ट्र में बहुत सारे समसामयिक मुद्दे हैं, लेकिन वे उन पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, इसके बजाय, वे 300 साल पुरानी घटना को मुद्दा बना रहे हैं, जो कि एक गैर-मुद्दा है।' घटना के बारे में: औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर एक दक्षिणपंथी संगठन

द्वारा किए गए आंदोलन के दौरान मुस्लिम समुदाय की पवित्र पुस्तक को जलाए जाने की अफवाहों के बीच मध्य नागपुर में सोमवार देर रात दो समूहों के बीच झड़प हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हिंसा में करीब 40 पुलिसकर्मी और पांच नागरिक घायल हो गए। नागपुर के पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंगल ने मंगलवार को कहा कि 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है और हिंसा के संबंध में पांच प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

2017 મરીન ડ્રાઇવ દુર્ઘટના

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेल मंत्री से वानस्पतिक अवस्था में पड़ी महिला के लिए 5 करोड़ रुपये के मुआवजे पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट महिला के पिता द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी), मुंबई के फरवरी 2021 के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसे ब्याज के साथ 69.92 लाख रुपये और 1.5 करोड़ रुपये की राशि देने का आदेश दिया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में रेल मंत्री से 25 वर्षीय महिला के लिए 5 करोड़ रुपये के अंतिम निपटान दावे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और निर्णय लेने को कहा है, जो आठ साल पहले दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव पर पश्चिमी रेलवे के स्वामित्व वाली इनोवा कार से टकराने के बाद से लगातार बेहोशी की हालत में है। यह दुर्घटना 28 मई, 2017 को हुई थी, जब निधि राजेश जेटमलानी, तब 17 वर्ष की थी, मरीन प्लाजा होटल के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड या मरीन ड्राइव के उत्तरी हिस्से को पार कर रही थी। वह कक्षा 12 में प्रवेश लेने के लिए सड़क के ठीक नीचे के सी कॉलेज जा रही थी। बॉम्बे हाईकोर्ट महिला के पिता द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी), मुंबई के फरवरी 2021 के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसे ब्याज के साथ 69.92 लाख रुपये और 1.5 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी, जिसका उपयोग उसके भविष्य के चिकित्सा



और अन्य खर्चों के लिए किया जाएगा। अक्टूबर 2022 में, उच्च न्यायालय ने पिता को अपील लंबित रहने तक पश्चिमी रेलवे द्वारा अदालत में जमा किए गए 1.15 करोड़ रुपये निकालने की अनुमति दी। 16 मार्च को जस्टिस गिरीश एस कुलकर्णी और अद्वैत एम सेठना की पीठ ने इसे 'दुर्लभतम में से दुर्लभतम मामला' करार दिया। इसने कहा कि दुर्घटना का खामियाजा उसके सिर को भुगतना पड़ा, 'जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क को गंभीर क्षति पहुंची, जिसके बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए भी चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले एक सामान्य व्यक्ति को काफी हिम्मत की जरूरत होती है'। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का प्रभाव इतना भयानक था कि इसने उसकी जान ले ली और उसे लगातार निष्क्रिय अवस्था में डाल दिया। इस खुश और होनहार लड़की की तस्वीरें और उसकी वर्तमान स्थिति किसी को भी बहुत दुख और नाखुशी दे सकती

है, फिर निधि की पीड़ा और माता-पिता के परिवार के सदस्यों की मानसिक स्थिति क्या होगी, 'उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की न्यायालय ने उसकी स्थिति की तुलना दिवंगत अरुणा शानबाग से की, जो 40 से अधिक वर्षों तक लगातार निष्क्रिय अवस्था में थी। इसने इस बात पर जोर दिया कि न केवल पीड़िता बल्कि उसके पूरे परिवार द्वारा अनुभव की गई पीड़ा 'कल्पना से परे' थी इसने कहा, 'किसी भी तरह से पैसा इस छोटी लड़की की पीड़ा और उसके परिवार के सदस्यों के आघात और दर्द की भरपाई नहीं कर सकता।' न्यायाधीशों ने कहा कि उसके देखभाल करने वाले माता-पिता ने अपनी बेटी के लिए महंगी चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इसने कहा, 'इन परिस्थितियों में धन/निधि की बढ़ती आवश्यकता दर्द और पीड़ा से वास्तविक राहत नहीं हो सकती है और यह केवल एक कम करने वाला कारक होगा।

'आवश्यक 'अत्याधिक व्यय', महिला की पीड़ा और उसके माता-पिता की पीड़ा को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि उसके लिए पुरस्कार राशि 'निश्चित रूप से अपर्याप्त' थी। पीठ ने कहा कि यह निपटान के लिए एक 'उपयुक्त मामला' था।

पिता ने 'उचित रुख' अपनाया और पहले भुगतान की गई राशि को छोड़कर, 5 करोड़ रुपये में इसे निपटाने का प्रस्ताव रखा। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह 'पूरी तरह से आश्वस्त' है कि प्रतिवादी, इसे 'मानव पीड़ा का गंभीर मामला' मानते हुए, अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तावित राशि का निपटान करने में उदारता दिखाएंगे। यदि इस राशि को उचित समझीता माना जाता है, तो न्यायालय ने कहा, 'न तो अपीलकर्ता के वर्षों के कष्टों और न ही परिवार के कष्टों की किसी भी तरह से भरपाई की जा सकती है। इसलिए, यह उचित होगा कि कार्यवाही को समाप्त कर दिया जाए।' अगली सुनवाई 20 मार्च को निर्धारित करते हुए न्यायालय ने प्रतिवादी अधिकारियों से उच्चतम स्तर पर निर्देश लेने का अनुरोध किया। न्यायालय ने कहा, 'रेलवे के कैबिनेट मंत्री, जो हमारी राय में मामले के तथ्यों पर विचार करेंगे और सहानुभूति रखते हुए इस पर निर्णय लेंगे, बिना इसे मिसाल के रूप में देखे।'

बीएमसी ने छत्रपति शिवाजी मार्केट और वर्ली डामर प्लांट में प्रमुख भूखंडों के लिए फिर से निविदा जारी की, राजस्व अनुमान घटाकर 1,100 करोड़ किया



बीएमसी ने दो प्रमुख संपत्तियों की नीलामी पुनः शुरू की है - एक फोर्ट स्थित छत्रपति शिवाजी मार्केट में तथा दूसरी वर्ली डामर प्लांट में स्थित है। हालांकि, पहले कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बाद,

बीएमसी ने इन भूखंडों के 30 साल के पट्टे के लिए अपने अनुमानित राजस्व को 4,000 करोड़ रुपये से घटाकर 1,100 करोड़ रुपये कर दिया है। बीएमसी ने शुरुआत में तीन प्रमुख भूखंडों के लिए निविदाएँ आमंत्रित की थीं: फोर्ट में छत्रपति शिवाजी मार्केट, वर्ली डामर प्लांट और दिसंबर 2024 में मालाबार हिल में बेस्ट सबस्टेशन पर एक भूखंड। स्थानीय निवासियों के कड़े विरोध का सामना करने के बाद मालाबार हिल भूखंड की नीलामी रद्द कर दी गई, जबकि नागरिक निकाय ने शेष दो संपत्तियों की नीलामी की योजना पर आगे बढ़ गए। संशोधित निविदा के अनुसार, 8,116.11 वर्ग मीटर में फैले मार्केट प्लांट का आधार मूल्य घटाकर 428 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पहले 2,069 करोड़ रुपये तक अनुमानित था। इसी तरह, वर्ली डामर प्लांट भूखंड, जो 10,847 वर्ग मीटर में फैला है, का आधार मूल्य अब 755 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि पहले इसका मूल्यांकन 2,175 करोड़ रुपये था। एक वरिष्ठ नगर निगम अधिकारी ने कहा, 'स्कीमों में यह बदलाव बीएमसी द्वारा मूल्य निर्धारण ढांचे को संशोधित करने के निर्णय का परिणाम है, जो अब अधिकतम उपयोग योग्य एफएसआई के बजाय स्वीकृत क्षेत्रीय फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) पर आधारित है।' एलएंडटी, गोदेरेज प्रॉपर्टीज, वेलस्पन वर्ल्ड, एचएन सफ़ल, रनवाल डेवलपर्स, डीबी रियल्टी जैसी उल्लेखनीय कंपनियों और विभिन्न आर्किटेक्चरल फर्मों के प्रतिनिधियों ने पिछले साल आयोजित प्री-बिड मीटिंग के दौरान रुचि व्यक्त की थी। उन्होंने इन प्रमुख भूखंडों को 30 साल के पट्टे पर हासिल करने की संभावना तलाशी, लेकिन अंततः बोलियाँ प्रस्तुत नहीं कीं। यह पहली बार है जब बीएमसी ने अपने भूखंडों को 30 साल की अवधि के लिए पट्टे पर देने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें अतिरिक्त 30 वर्षों के लिए नवीनीकरण का विकल्प भी शामिल है। इन पट्टों से प्राप्त आय से नगर निकाय द्वारा किए गए विभिन्न बुनियादी ढाँचे संबंधी पहलों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।

**ठाणे कांग्रेस ने 10 दिन के कूड़े
के ढेर पर विरोध की चेतावनी
दी; नागरिक कार्रवाई की मांग**

ठाणे कांग्रेस पार्टी के नेता ने दस दिनों तक ठाणे शहर से कूड़ा न उठाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सत्तारूढ़ दल और नागरिक निकाय द्वारा समस्या का समाधान करने में विफल रहने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी।टीएमसी अधिकारियों के अनुसार, सीपी तलाव कचरा स्थानांतरण केंद्र एक अंतरिम स्थल के रूप में कार्य करता है जहां कचरे को मिनी वाहनों में लाया जाता है, अस्थायी रूप से डंप किया जाता है, और फिर दैघर प्रसंस्करण संयंत्र में स्थानांतरण के लिए भारी वाहनों पर लोड किया जाता है। इस व्यवस्था के बावजूद, स्थानीय लोगों का दावा है कि साइट पर बड़ी मात्रा में कचरा रहता है, जिससे स्वच्छ हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वे इसके पूर्ण स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं।ठाणे कांग्रेस के नेता विक्रान्त चव्हाण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले दस दिनों से शहर की आवासीय सोसायटियों से कचरा नहीं उठाया गया है और यह सड़क के किनारे जमा हो गया है। चव्हाण ने इस बात पर जोर दिया कि ठाणे नगर निगम की सत्तारूढ़ पार्टी ने आशवासन के बावजूद शहर की स्वच्छता बढ़ाने या कचरा उठाने की दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। चव्हाण ने जोर देकर कहा कि ठाणे नगर निकाय की सत्तारूढ़ पार्टी के पास कचरा निपटान की कोई योजना नहीं है।चव्हाण ने संबंधित प्रशासन को चेतावनी दी कि कचरा उठाने के मुद्दों को लेकर कांग्रेस और ठाणेकर गुरुवार को ठाणे नगर निगम के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

उद्धव ठाकरे ने PM मोदी से की थी मुलाकात, कहा- वह गठबंधन बनाना चाहते थे, लेकिन..., शिंदे ने विधानमंडल में फोड़ा रहस्य बम



मुंबई: मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर जारी विवाद के बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना(UBT) के एमएलसी अनिल परब पर सीधे तौर से मंगलवार को तंज कसा। इसके बाद राज्य विधानपरिषद में सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। नागपुर में एक दिन पहले हुई हिंसा के संबंध में विधानपरिषद में शिंदे ने मुगल बादशाह औरंगजेब के कथित महिमामंडन पर सवाल उठाया। परब ने आरोप लगाया कि वह वहां(शिंदे बीजेपी संग) इसलिए गए क्योंकि उन्हें एक नोटिस मिला था। इसके बाद उपमुख्यमंत्री शिंदे बेहद आक्रामक नजर आए। उन्होंने चेतावनी दी कि परब साहब, मैं आपका इतिहास जानता हूं। मुझे सब पता है। इसलिए मुझे और अधिक बात करने पर मजबूर मत करो।

उन्होंने कहा कि हम पिछले ढाई साल में किए गए काम के कारण वापस आए हैं। आपने विपक्ष के नेता का पद खो दिया। मैं तुम्हें कुछ अंदरूनी खबर बताना चाहता हूँ। उनके नेता मोदी साहब से मिलने गए। मैंने कहा, मुझे खेद है। 'शेर की खाल पहनने से भेड़िया शेर नहीं बन जाता'

एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम आपके पास फिर आएंगे। लेकिन यहां तो मामला पलट गया। आप भी चले गए (त्योहारों का जिक्र करते हुए)। जब

तुम्हें नॉटिस मिला तो तुम जा चुके थे। तुमने कहा था, मुझे इससे बाहर निकालो। लेकिन आप पलट गए। हमने जो किया खुलेआम किया। हम छुपकर नहीं बैठे। जब शिवसेना खतरे में थी, बालासाहेब के विचार और हिंदुत्व खतरे में थे, तब आपकी सरकार गिरा दी गई। ऐसा करने के लिए शेर जैसा दिल चाहिए। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि शेर की खाल पहनने से भेड़िया शेर नहीं बन जाता। उद्धव ठाकरे पर निशाना शिंदे

ने आगे कहा कि परब साहेब, मैं आपका इतिहास जानता हूँ। मुझे सब पता है। अंडे और जर्दी ज्ञात हैं। मुझे इस बात का अंदाजा है कि कौन किस मकसद से कहां गया था। मैंने जो किया, खुलेआम किया। मैंने आपके पार्टी प्रमुख से शिवसेना और बीजेपी के साथ गठबंधन बनाने को कहा था। तो क्या मैं मुख्यमंत्री बनने वाला था? फिर भी, उन्हें पांच बार बताया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी आकर्षक क्यों थी? बालासाहेब ने कहा था कि कांग्रेस के साथ मत जाओ। तुम क्यों गए? हमने सत्ता छोड़ दी, हमने मंत्री पद छोड़ दिए। 'आपने बालासाहेब के विचारों को त्याग दिया' शिंदे ने ठाकरे सेना पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, फिर भी 8 लोगों ने अपने मंत्री पद छोड़ दिए। आप 2019 में कांग्रेस के साथ सत्ता में आए।

आठ लाख वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर सबसे ऊपर, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट ने चेताया

बढ़ते वैश्विक तापमान के पीछे मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियां ही जिम्मेदार हैं। विकास की तेज रफ्तार और औद्योगिकीकरण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के मौजूदा स्तर ने पिछले आठ लाख वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। साथ ही चेताया कि यह जलवायु परिवर्तन का संकट काल है, जिसके प्रभाव सदियों तक बने रह सकते हैं। इसका अर्थ है कि वर्तमान पीढ़ी की गलतियों का खामियाजा आने वाली कई नस्लों को भुगतना पड़ेगा।

रिपोर्ट में इस बात पर दिया जोर.. डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट में बढ़ते तापमान के कारण उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2024 जलवायु

अस्थिरता के लिहाज से इतना उथल-पुथल भरा रहा कि यह जलवायु इतिहास में दर्ज हो गया। 2024 पहला ऐसा वर्ष रहा जब औसत वैश्विक तापमान औद्योगिक युग से पहले की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा इस दौरान तापमान में 1.55 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले 175 वर्षों के जलवायु इतिहास में इसे सबसे गर्म वर्ष बनाता है।

तापमान वृद्धि पर एक नजर
वैश्विक तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि के लिए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि और अल नीनो प्रमुख रूप से जिम्मेदार थे। रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा अब पिछले आठ लाख वर्षों में सबसे अधिक हो चुकी है। 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 420 पीपीएम तक पहुंच गया, जो 2022 की तुलना में 2.3 पीपीएम अधिक



था। औद्योगिक क्रांति (1750) के मुकाबले यह 151 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है, जो वायुमंडल में 3,27,600 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के बराबर है। 2024 में भी इन गैसों के स्तर में बढ़ोतरी जारी रही।

महासागरों में बढ़ती गर्मी से हर वर्ष नए रिकॉर्ड बने
धरती के साथ महासागर भी लगातार गर्म हो रहे हैं। बीते आठ वर्षों के दौरान महासागरों में रिकॉर्ड स्तर पर गर्मी बढ़ी है। ग्रीनहाउस गैसों से उत्पन्न 90 फीसदी अतिरिक्त गर्मी समुद्रों में समा



जाती है। 2024 में समुद्री तापमान पिछले 65 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। महासागर अब 1960 से 2005 की तुलना में दोगुनी तेजी से गर्म हो रहे हैं, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है। यह समुद्री जीवन को नुकसान

पहुंचाने के साथ-साथ महासागरों की कार्बन अवशोषित करने की क्षमता को भी कम कर रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ऐसे बदलाव हैं जिन्हें सैकड़ों या हजारों सालों तक पलटा नहीं जा सकता। यदि कार्बन उत्सर्जन को कम कर भी दिया जाए तो भी महासागर 21वीं सदी में गर्म होते रहेंगे। **उबरने में लगेंगी सदियां**
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस रिपोर्ट के बाद वैश्विक नेताओं से अपील की है कि इस दिशा में निवेश ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। उनका कहना है कि हमारा ग्रह संकट के अधिक संकेत दे रहा है। उन्होंने वैश्विक नेताओं से स्वच्छ अक्षय ऊर्जा साधनों में निवेश बढ़ाने की अपील की है। इसका असर धीमे जहर की तरह हो रहा है। अगर हम इसका उचित समाधान निकालने में विफल रहे तो जलवायु के घावों को भरने में सदियां लग जाएंगी।

भारत पर व्यापार युद्ध का खास असर नहीं, 6.5% तेजी से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था; फिच ने कहा- US की नीतियां खतरनाक

अमेरिकी सरकार की नीतियों के कारण व्यापार युद्ध के कारण अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा है। हालांकि, एक रिपोर्ट का दावा है कि भारत पर व्यापार युद्ध का खास असर नहीं होगा और देश की अर्थव्यवस्था 6.5 फीसदी रफ्तार से बढ़ेगी। फिच की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की आक्रामक व्यापार नीतियां दुनिया के लिए बड़ा जोखिम हैं।



टैरिफ वार के कारण दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं के मंदी में फंसने का जोखिम बढ़ गया है। हालांकि, भारत पर इस व्यापार युद्ध का गहरा असर नहीं होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5 फीसदी की रफ्तार से बढ़ेगी। 2026-27 में आर्थिक वृद्धि दर मामूली घटकर 6.3 फीसदी रह सकती है। फिच रेटिंग्स ने ग्लोबल इकॉनॉमिक आउटलुक (जीईओ) के मार्च संस्करण में कहा, अमेरिका की आक्रामक व्यापार नीतियां एक बड़ा जोखिम बनकर सामने आई हैं। इससे भारत की आर्थिक वृद्धि दर

2025-26 की तुलना में 2026-27 में थोड़ी नीचे आ सकती है। हालांकि, बाहरी मांग पर कम निर्भरता और पर्याप्त आत्मनिर्भरता के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापार युद्ध के व्यापक असर से बची रहेगी। रेटिंग एजेंसी ने कहा, पूंजीगत खर्च सहित निजी और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण भारतीय जीडीपी की वृद्धि दर में सुधार हुआ है। यह चालू वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के 5.4 फीसदी से बढ़कर चौथी तिमाही में 6.2 फीसदी पर पहुंच गई है। इस वृद्धि में कृषि क्षेत्र का भी योगदान है। औसत से अधिक

मानसूनी बारिश के कारण खरीफ फसल का उत्पादन बढ़ा है। मजबूत निर्यात से वृद्धि को समर्थन ग्लोबल इकॉनॉमिक आउटलुक के मुताबिक, निर्यात में मजबूत वृद्धि और आयात में गिरावट के संयोजन से इस साल जीडीपी वृद्धि को समर्थन मिला है। शुद्ध निर्यात में वृद्धि से 2025-26 और 2026-27 में भी अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। कर स्लैब में संशोधन और बढ़ी करमुक्त आय से उपभोक्ताओं की बचत में इजाफा होगा। इससे खर्च और विकास को बढ़ावा मिलेगा। कारोबारी भरोसा शीर्ष पर, बढ़ेगा

पूंजीगत खर्च
फिच ने कहा, भारत में कारोबारी भरोसा उच्च स्तर पर बना हुआ है। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि निजी क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक कर्ज में दहाई अंकों की वृद्धि जारी रहेगी। रेटिंग एजेंसी ने कहा, केंद्रीय बजट में सार्वजनिक पूंजीगत खर्च के उच्च आवंटन से जीडीपी को समर्थन मिलेगा। इन कारकों के अलावा आरबीआई की ओर से ब्याज दरों में कटौती से लागत में कमी आएगी, जिससे 2025-26 और 2026-27 में पूंजीगत खर्च में तेजी आएगी। इस साल दो बार और घटेगी रेपो दर खुदरा महंगाई के फरवरी, 2025 में घटकर चार फीसदी से नीचे आने के बीच फिच का मानना है कि दिसंबर, 2026 तक मुद्रास्फीति मामूली बढ़कर 4.3 फीसदी पहुंच जाएगी, क्योंकि आरबीआई ने रेपो दर में कटौती शुरू कर दी है। उम्मीद है कि इस साल रेपो दर में दो बार और कटौती होगी, जिससे यह वर्तमान के 6.25 फीसदी से घटकर दिसंबर, 2025 तक 5.75 फीसदी पर आ जाएगी।

आभूषण ऋण को लेकर RBI के नए नियम पर कांग्रेस सांसद चिंतित, वित्त मंत्री से की नीति बदलने की मांग

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर आभूषण ऋण के पुनर्भुगतान को लेकर रिजर्व बैंक की ओर से किए गए नीतिगत बदलावों पर चिंता जताई है। सांसद ने वित्त मंत्री से नीति में हुए बदलाव के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि आभूषण ऋण को चुकाने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में नीतिगत बदलाव किए हैं। इसका छोटे व्यापारियों, किसानों और कम आय वाले व्यक्तियों सहित समाज के कमजोर वर्गों पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। सांसद ने कहा कि पुरानी व्यवस्था के तहत ग्राहकों को ऋण अवधि के दौरान अपने आभूषण ऋण पर केवल अर्जित ब्याज चुकाने की अनुमति थी। ऋण अवधि के अंत में उधारकर्ता पूरी मूल राशि चुकाए बिना अपने ऋण का नवीनीकरण करा सकते थे। इससे धन की तत्काल आवश्यकता वाले लोगों को वित्तीय राहत मिली है। इसके चलते छोटे व्यवसाय और व्यक्ति को अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सके। टैगोर ने कहा कि अब नए नियम के अनुसार ग्राहकों को लोन अवधि के अंत में ब्याज सहित पूरी मूल राशि चुकानी होगी। इसके बाद ही वे अपने गहनों को नए लोन के लिए रिन्यू या गिरवी रख सकते हैं। इस बदलाव ने चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि इससे उन उधारकर्ताओं के लिए काफी मुश्किलें पैदा होने की संभावना है जो पहले से ही वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के लोग आपातकालीन निधियों के लिए गहनों के ऋण पर निर्भर हैं। उनके पास एक बार में मूलधन और ब्याज दोनों चुकाने की वित्तीय क्षमता नहीं है। नए नियम से कई लोगों के लिए वित्तीय संकट खड़ा हो सकता है। तमिलनाडु से सांसद ने कहा कि छोटे व्यवसाय, किसान और कम आय वाले परिवार विशेष रूप से इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि अचानक पुनर्भुगतान की मांग उन्हें ऋण चुकाने में चूक करने के लिए मजबूर कर सकती है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है और वे और अधिक कर्ज में डूब सकते हैं। सांसद ने वित्त मंत्री से कहा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और आरबीआई से इस नियम पर पुनर्विचार करने या इसमें संशोधन करने का अनुरोध करें। इस पर पुनर्विचार करने से न केवल समाज के कमजोर वर्गों को राहत मिलेगी, बल्कि आभूषण ऋण उन लोगों के लिए सुलभ रहेगा जिन्हें अपने अस्तित्व और आजीविका के लिए धन की तत्काल आवश्यकता है।

40 की हो, आलिया भट्ट की मां का रोल करोगी? एल्विश यादव ने उड़ाया अंकिता लोखंडे की उम्र का मजाक



यूट्यूबर और 'बिग बॉस ओटीटी 2' विनर एल्विश यादव अक्सर ही कुछ ऐसा बोल देते हैं कि विवादों में आ जाते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपने पॉडकास्ट में अंकिता लोखंडे और विक्की जैन को बुलाया था। तब एल्विश ने अंकिता की उम्र का मजाक उड़ाया था, जिसका वीडियो दोबारा सामने आया है, और इसे देख यूजर्स भड़क गए हैं। उन्होंने एल्विश की क्लास लगा दी। एल्विश यादव ने अपने पॉडकास्ट में अंकिता लोखंडे को बुलाया था, और बातचीत के दौरान एक्ट्रेस को एज शेम किया। एल्विश यादव ने अंकिता से पूछा था कि विकीपीडिया आपकी उम्र 40 साल बताता है, तो आलिया भट्ट के साथ मूवी करोगी? मां का रोल करोगी? यह सुनकर अंकिता भी हैरान रह गईं। उन्होंने एल्विश यादव की ओर अजीब लुक से देखा, और फिर पूछा, 'क्यों? 40 साल की लेडी बूढ़ी हो जाती है?' अंकिता लोखंडे ने आगे कहा, 'मैं तो कहीं से भी बूढ़ी नहीं लगती हूँ। नहीं, मैं कहीं से भी नहीं लगती आलिया भट्ट की मां।' इसके बाद एल्विश फिर भी यही पूछते रहते हैं कि क्या अंकिता कभी मां का रोल प्ले करेंगी, तो एक्ट्रेस बताती हैं कि उन्होंने बहुत ही यंग एज में 'पवित्र रिश्ता' में मां का रोल किया था। इसके बाद एल्विश फिर पूछ लेते हैं कि क्या अंकिता फिल्म में आलिया की मां का रोल करेंगी, तो अंकिता ने जवाब दिया, 'बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं कहीं से आलिया की मां नहीं लगती।'

फिल्मी परिवार में जन्म, फिल्मी माहौल में परवरिश फिर भी नहीं चला इन सितारों का करियर

इन दिनों फिल्म 'नादानियां' में इब्राहिम अली खान और और खुशी कपूर को उनकी एक्टिंग के लिए काफी ट्रोल किया जा रहा है। कई सितारे उनके बचाव में आए हैं। आने वाली फिल्मों में इन दोनों स्टारकिड्स का करियर कैसा होगा और फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करेंगे, इसका जवाब तो समय के साथ मिलेगा। मगर, इस बहाने फिल्मावल उन कुछ स्टारकिड्स के बारे में भी जान लेते हैं, जिनका सिक्का फिल्मी दुनिया में नहीं चला। फिल्मी परिवार में जन्म, फिल्मी माहौल में परवरिश के बावजूद दर्शकों को ये लुभा नहीं पाए। जानते हैं...

उदय चोपड़ा

उदय चोपड़ा दिवंगत निर्माता-निर्देशक यश चोपड़ा के बेटे हैं। उनके यशराज फिल्मस के बैनर तले कितने ही कलाकार सुपरस्टार बने, मगर उदय चोपड़ा का करियर नहीं चल पाया। उदय चोपड़ा ने अपना करियर फिल्म 'मोहब्बते' से शुरू किया था। फिल्म सुपरहिट थी, लेकिन यह मल्टीस्टारर फिल्म थी।



शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय जैसे सितारे अहम रोल में थे। इस फिल्म के बाद उदय चोपड़ा की कोई भी फिल्म दर्शकों पर जादू नहीं चला सकी।

तुषार कपूर

सुपरस्टार जितेंद्र और शोभा कपूर के बेटे तुषार कपूर का नाम भी इस लिस्ट में है। ऐसा नहीं है कि तुषार कपूर को फिल्में नहीं मिलीं, वे कई चर्चित फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। लेकिन, बतौर लीड एक्टर यूजर्स उन्हें स्वीकार नहीं कर पाए। तुषार ने फिल्म 'मुझे कुछ कहना है' से डेब्यू किया था। इसके बाद भी वो कई

फिल्मों में नजर तो आए, लेकिन अपनी एक्टिंग की छाप नहीं छोड़ पाए।

तनीषा मुखर्जी

दिग्गज अदाकारा तनुजा की बड़ी बेटी अभिनेत्री काजोल की अदाकारी के दर्शक कायल हैं। परदे से लेकर ओटीटी तक उनका जलवा है। वहीं, उनकी छोटी बहन तनीषा मुखर्जी का करियर खास नहीं रहा। उनकी पहली फिल्म 'Sssshhh...' थी। इसके बाद तनीषा ने अपने करियर में कई बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन बतौर अभिनेत्री उनकी कोई भी फिल्म परदे पर जादू नहीं चला

सकी। तनीषा को अक्सर बॉलीवुड पार्टियों और इवेंट में देखा जाता है।

रिंकी खन्ना

इसी तरह अभिनेत्री रिंकी खन्ना का करियर भी रहा। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और दिग्गज अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की छोटी बेटी रिंकी खन्ना को दर्शकों का प्यार नहीं मिला।

उनकी बड़ी बहन दिवंगत खन्ना ने कई फिल्मों में काम किया और सफल रही। हालांकि, अब दिवंगत भी इंडस्ट्री से दूर हैं और राइटर बन गई हैं।

फरदीन खान

दिग्गज एक्टर फिरोज खान के बेटे फरदीन खान का फिल्मी करियर भी सुस्त रहा। डैशिंग लुक और आकर्षक पर्सनैलिटी के बावजूद वे दर्शकों का दिल नहीं जीत पाए। हालांकि, बीते वर्ष उन्होंने ओटीटी पर सीरीज 'हीरामंडी' से डेब्यू किया। इसमें उनके किरदार की काफी तारीफ हुई।

आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट, चहल सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज; रिकॉर्ड

आईपीएल के 18वें सत्र की शुरुआत में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 22 मार्च से टूर्नामेंट का आगाज होगा, पहला मैच गत विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। इस साल 10 टीमों के बीच 13 स्थानों पर 65 दिनों में कुल 74 मैच खेले जाएंगे, जिसमें 70 लीग राउंड और चार प्लेऑफ के मुकाबले होंगे। फाइनल समेत प्लेऑफ के सभी मुकाबले 20 से 25 मई तक हैदराबाद और कोलकाता में खेले जाएंगे। हैदराबाद 20 मई, 2025 और 21 मई को क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर की मेजबानी करेगा। इसके बाद कोलकाता 23 मई, 2025 को क्वालिफायर 2 की और 25 मई को फाइनल की मेजबानी करेगा। आईपीएल 2025 में कुल 12 डबल हेडर्स हैं। डबल हेडर वाले दिन पहला मैच दोपहर साढ़े तीन बजे से और दूसरा मैच शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा। आईपीएल शुरू होने से पहले हम आपको सबसे ज्यादा रन, विकेट, चौके और छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों के बारे में

ग्रुप-ए	ग्रुप-बी
चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके)	मुंबई इंडियंस (एमआई)
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी)	गुजरात टाइटंस (जीटी)
राजस्थान रॉयल्स (आरआर)	दिल्ली कैपिटल्स (डीसी)
पंजाब किंग्स (पीबीकेएस)	सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच)
कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर)	लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी)

बता रहे हैं... विराट कोहली के नाम सबसे ज्यादा रन आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली भले ही अपनी टीम को कभी ट्रॉफी नहीं जिता पाए लेकिन उनके निजी प्रदर्शन में कभी कमी नहीं आई है। इसकी गवाही आंकड़े दे रहे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 2008 में अपने करियर की शुरुआत की थी। अब तक वह आरसीबी का ही हिस्सा हैं।

252 मैचों में किंग कोहली ने 131.97 के स्ट्राइक रेट से 8004 रन बनाए। सर्वाधिक रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर शिखर धवन हैं जिन्होंने पिछले साल ही संन्यास का एलान किया था। 221 मैचों में उनके नाम 6769 रन दर्ज हैं। रोहित शर्मा 6628 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं। सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं चहल स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल भले ही भारतीय टीम में अपनी जगह

बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं लेकिन आईपीएल में वह एक बार फिर चमकने के लिए तैयार हैं। इस बार वह पंजाब किंग्स के लिए खेलते नजर आएंगे। इससे पहले वह मुंबई इंडियंस, आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल चुके हैं। दाएं हाथ के इस

गेंदबाज के नाम आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 160 मैचों में 7.84 की इकोनॉमी से 205 विकेट लिए हैं। क्रिस गेल के नाम सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 142 मैचों में 357 छक्के लगाए। 'यूनिवर्स बॉस' गेल इस लीग में चार टीमों का हिस्सा रहे। इनमें केकेआर, किंग्स इलेवन पंजाब, पंजाब किंग्स और आरसीबी शामिल हैं। इस मामले में दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः रोहित शर्मा (280) और

विराट कोहली (272) हैं। किंग कोहली के पास आगामी टूर्नामेंट में हिटमैन को पीछे छोड़ने का सुनहरा मौका है। सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज हैं शिखर धवन आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज शिखर धवन ने पिछले साल संन्यास का एलान किया था। वह सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 222 मैचों में 764 चौके लगाए। इस मामले में दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं। उन्होंने अबतक खेले 252 मैचों में 705 चौके जड़े हैं। आगामी सत्र में वह धवन को पीछे छोड़ सकते हैं।

इन 13 स्थानों पर खेले जाएंगे मैच

चेन्नई स्टेडियम (चेन्नई)	एमवाईएस स्टेडियम (न्यू चंडीगढ़, मुल्तानपुर)
नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद)	सवाई मानसिंह स्टेडियम (जयपुर)
इंडन गार्डेंस (कोलकाता)	चित्रास्वामी स्टेडियम (बेंगलुरु)
अरुण जेटली स्टेडियम (नई दिल्ली)	राजीव गांधी स्टेडियम (हैदराबाद)
इकाना स्टेडियम (लखनऊ)	एचपी क्रिकेट स्टेडियम (धर्मशाला)
वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई)	बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम (गुवाहाटी)
	वाईएसआर स्टेडियम (विशाखापत्तनम)

रात में बच्चे के खरटे को न करें नजरअंदाज, हो सकता है यह किसी गंभीर समस्या का संकेत

बच्चों में खरटे लेने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं, कुछ साधारण और अस्थायी होती हैं, जबकि कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याओं की ओर इशारा करती हैं। आइए जानते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं और कब आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है।

अगर आपका बच्चा रात में खरटे लेता है, तो इसे हल्के में न लें। हालांकि कभी-कभार खरटे आना सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर ये समस्या लगातार बनी रहती है या खरटे बहुत तेज होते हैं, तो यह किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। बच्चों में खरटे लेने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं, कुछ साधारण और अस्थायी होती हैं, जबकि कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याओं की ओर इशारा करती हैं। आइए जानते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं और कब आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है।

बच्चों में खरटे लेने के सामान्य कारण

हर खरटा समस्या का संकेत नहीं होता। लेकिन अगर खरटे बार-बार आ रहे हैं, तो इन सामान्य कारणों को नजरअंदाज न करें:

सर्दी-जुकाम या एलर्जी
नाक बंद होने या बलगम जमा होने की वजह से सांस का मार्ग अवरुद्ध



हो सकता है, जिससे खरटे आते हैं।

बड़े हुए ऐडिनाइड्स और टॉन्सिल्स

अगर टॉन्सिल्स और ऐडिनाइड्स बड़े हो जाते हैं, तो गले में सांस के रास्ते को संकरा कर सकते हैं, जिससे खरटे आ सकते हैं।

ओवरवेट या मोटापा

अधिक वजन के कारण गले और गर्दन के आसपास अतिरिक्त फैट जमा हो सकता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो सकता है और खरटे शुरू हो सकते हैं।

स्लीपिंग पोजीशन

अगर बच्चा पीठ के बल सोता है, तो जीभ और ऊपरी तालू पीछे की ओर गिर सकते हैं, जिससे सांस का मार्ग संकरा हो जाता है और खरटे आने लगते हैं।

कब सतर्क होने की जरूरत है?

- अगर आपके बच्चे के खरटे के साथ निम्नलिखित लक्षण भी दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें:
- खरटों के दौरान सांस रुकना
- दिनभर सुस्ती और थकावट महसूस करना
- ध्यान केंद्रित करने में परेशानी

- रात में पसीना आना
- मुंह से सांस लेना या बार-बार जागना
- सोते समय सांस फूलना या घुटन महसूस होना

क्या करें?

अगर आपके बच्चे को खरटे आ रहे हैं, तो घबराएं नहीं, कुछ आसान बदलाव और सावधानियां इस समस्या को हल कर सकती हैं:

- सोने का रूटीन व्यवस्थित करें – हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें।
- नाक की सफाई करें – सोने से पहले बच्चे की नाक को साफ करें ताकि सांस का मार्ग खुला रहे।
- वजन नियंत्रण में रखें – बच्चे का खानपान संतुलित करें और फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान दें।
- एलर्जी से बचाव करें – बच्चे के सोने की जगह को साफ रखें और धूल या पालतू जानवरों के संपर्क से बचाएं।
- डॉक्टर से सलाह लें – अगर समस्या बनी रहती है या गंभीर लक्षण दिखते हैं, तो डॉक्टर से संपर्क करें।

क्यों खास है बटर गार्लिक नान? अपने स्वाद और पॉपुलैरिटी से कैसे बनाई इंटरनेशनल पहचान



भारतीय खाने की एक अलग ही पहचान है जहां पर एक से बढ़कर डिशेज केवल भारत ही नहीं दुनिया में स्थान रखती है। आज भारत के लिए रसोई का स्वाद इंटरनेशनल रसोई में छाया है। यहां पर हाल ही में ग्लोबल फूड गाइड Taste Atlas ने दुनिया की 50 बेस्ट ब्रेड की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत की एक सबसे पॉपुलर रोटी यानि बटर गार्लिक नान ने जगह बनाई है इस खास उपलब्धि से हर भारतीय का मन उत्साह से भर गया है। जानिए क्या है Taste Atlas की रैंकिंग और कैसे तैयार होती है यह पॉपुलर रोटी। आपको बताते चलें कि, यहां पर हम Taste Atlas के काम को समझें तो, यह एक तरह का ग्लोबल फूड गाइड है, जो दुनिया भर के खाने-पीने की चीजों को उनकी पॉपुलैरिटी और टेस्ट के आधार पर रैंकिंग देता है। यहां पर दुनियाभर के कई फूड्स की टेस्टिंग की जाती है इसके अलावा पब्लिक रिव्यू के आधार पर रेटिंग दी जाती है। इस बार Taste Atlas ने दुनियाभर की टॉप 50 ब्रेड्स की लिस्ट जारी की, जिसमें भारतीय बटर गार्लिक नान नंबर 1 बनी है। कैसी होती है बटर गार्लिक नान और कैसे बनाएं यहां पर बटर गार्लिक नान की खासियत जानें तो, यह अपनी सॉफ्ट और फ्लेकी टेक्सचर, बटर की मलाईदार परत और गार्लिक की लाजवाब खुशबू के लिए जानी जाती है और खाने के स्वाद में भी बेहतरीन है। तंदूर में पकाई गई ये ब्रेड हर तरह की ग्रेवी और करी के साथ बेहतरीन लगती है। इसे बनाने के लिए मैदा, दही, दूध, यीस्ट या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये सॉफ्ट और हल्की फलफी बनती है।

अमेरिकी शिक्षा विभाग को खत्म करने की तैयारी में ट्रंप, जल्द कर सकते हैं कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार (स्थानीय समयानुसार) को अमेरिकी शिक्षा विभाग को खत्म करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार (स्थानीय समयानुसार) को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं, जिसका उद्देश्य अमेरिकी शिक्षा विभाग को खत्म करना है। यह उनके चुनावी वादों में से एक था। यूएसए टुडे ने वरिष्ठ ट्रंप प्रशासन अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी।

ट्रंप इस आदेश पर व्हाइट हाउस में एक समारोह के दौरान हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें कई रिपब्लिकन गवर्नर और राज्य के शिक्षा आयुक्त शामिल होंगे। यूएसए टुडे के अनुसार, ट्रंप अपनी शिक्षा सचिव लिंडा मैकमैहन को यह निर्देश देंगे कि शिक्षा विभाग को बंद करें और शिक्षा से संबंधित

अधिकारों को राज्यों को लौटाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन सेवाओं, कार्यक्रमों और लाभों पर अमेरिकी नागरिक निर्भर हैं, उनकी रूपांतरित आपूर्ति जारी रहनी चाहिए।

यह आदेश ट्रंप के लिए परीक्षा होगा ट्रंप का यह नया आदेश राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा की एक नई परीक्षा होगा। इससे पहले उनकी सरकार ने अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएड) को बंद करने का प्रयास किया था, जिसे इस सप्ताह मैरीलैंड के संघीय जिला न्यायालय ने रोक दिया था। 1978 में कांग्रेस द्वारा एक कैबिनेट-स्तरीय एजेंसी के रूप में स्थापित शिक्षा विभाग इस आदेश के तुरंत बाद बंद



नहीं होगा।

विभाग को पूरी तरह खत्म करने के लिए कांग्रेस की कार्रवाई की आवश्यकता होगी। हाल के हफ्तों में, ट्रंप ने इस एजेंसी

के कर्मचारियों की संख्या कम कर दी है, लेकिन यह एजेंसी अभी भी काम कर रही है और स्कूलों के लिए महत्वपूर्ण संघीय वित्त पोषण कार्यक्रमों की निगरानी करती है।

व्हाइट हाउस के प्रिंसिपल डिप्टी प्रेस सचिव हैरिसन फील्ड्स ने यूएसए टुडे को दिए एक बयान में कहा कि यह आदेश रूमाता-पिता, राज्यों और समुदायों को सशक्त करेगा, जिससे सभी छात्रों के लिए परिणामों में सुधार होगा। कई राज्यों के गवर्नर होंगे शामिल एक व्हाइट हाउस अधिकारी के अनुसार, दिव्यांग छात्रों के लिए संघीय वित्त पोषण, कम आय वाले स्कूलों के लिए टाइल I

फंडिंग और संघीय छात्र ऋण भुगतान इस आदेश के तहत अपरिवर्तित रहेंगे। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसांटिस, वर्जीनिया के

गवर्नर ग्लेन यंगकिन, टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट और ओहायो के गवर्नर माइक डिवाइन सहित कई रिपब्लिकन गवर्नर इस हस्ताक्षर समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। रिपब्लिकन सांसद लंबे समय से संघीय सरकार पर स्थानीय और राज्य शिक्षा नीति पर नियंत्रण रखने का आरोप लगाते रहे हैं, हालांकि संघीय सरकार का स्कूल पाठ्यक्रम पर कोई नियंत्रण नहीं है।

ट्रंप का यह आदेश ऐसे समय आया है जब पिछले हफ्ते 1,300 से अधिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को सेवा समाप्ति नोटिस दिया गया था। यह फेडरल गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट द्वारा संघीय सरकार में की गई छंटनी के तहत किया गया था।

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने पनवेल बस स्टैंड परियोजना को तत्काल फिर से शुरू करने का आदेश दिया, विकास की समीक्षा की

मुंबई: महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने अधिकारियों को नए टेंडर जारी करके पनवेल बस स्टैंड पर तुरंत काम फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। परियोजना, जो 2018 से रुकी हुई है, ने मुंबई के बाहरी इलाके में तेजी से विकसित हो रहे शहर पनवेल में बढ़ते यात्री यातायात के कारण नए सिरे से आग्रह प्राप्त किया है। यह घोषणा बुधवार को राज्य परिवहन विभाग के कामकाज की समीक्षा के लिए विधान भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान हुई। बैठक में विक्रांत पाटिल, बालाजी कल्याणकर, विजय देशमुख और दौलत दरोंदा सहित कई विधायकों के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य सड़क

परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के महाप्रबंधक (निर्माण) और एडवीर अकाउंट्स देशमुख जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। चर्चा के दौरान विधायक विक्रांत पाटिल ने मौजूदा बुनियादी ढांचे पर बढ़ते दबाव पर प्रकाश डालते हुए पनवेल बस स्टैंड पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्री सरनाइक ने अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निर्माण बिना किसी देरी के शुरू हो। पनवेल के अलावा, मंत्री सरनाइक ने राज्य भर में कई अन्य लंबे समय से लंबित परिवहन परियोजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्र की लंबे समय से चली आ



रही मांग को पूरा करते हुए अधिकारियों को नांदेड़ के सांगवी में एक बस स्टैंड के निर्माण को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। नांदेड़ के विधायक बालाजी कल्याणकर ने प्रशासन से इस

आवश्यकता को पूरा करने के लिए तेजी से कार्य करने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त, मंत्री ने शाहपुर (ठाणे जिले) में एक नए बस बंदरगाह और सोलापुर शहर में केंद्रीय बस स्टैंड के विकास में तेजी लाने के महत्व पर

जोर दिया। आने वाले मानसून के मौसम को देखते हुए, उन्होंने यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए प्रमुख बस स्टेशनों पर अस्थायी शेड स्थापित करने का सुझाव दिया। बढ़ते शहरी केंद्रों के लिए आधुनिक परिवहन केंद्र

जैसे-जैसे पूरे महाराष्ट्र में शहरीकरण तेज हो रहा है, आधुनिक, अच्छी तरह से सुसज्जित बस टर्मिनलों की मांग काफी बढ़ गई है। विधायक दौलत दरोंदा (शाहपुर) और विजय देशमुख (सोलापुर) ने छात्रों और दैनिक यात्रियों सहित स्थानीय नागरिकों के लिए सुगम सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करने में इन परियोजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। मंत्री सरनाइक ने आश्वासन दिया कि राज्य परिवहन विभाग इन परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा और महाराष्ट्र के सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए समय पर निष्पादन सुनिश्चित करेगा।

मुंबई शहर को नया कलेक्टर मिला क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने 5 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को पांच और आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया और आंचल गोयल को मुंबई शहर का नया जिला कलेक्टर नियुक्त किया। 2014 बैच की आईएएस अधिकारी गोयल 31 जुलाई, 2023 को नागपुर नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालेंगी। उन्होंने नागपुर में अपनी पोस्टिंग से पहले परभणी के जिला कलेक्टर और रत्नागिरी जिला परिषद के सीईओ के रूप में कार्य किया। वह वर्तमान में नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएसएससीडीसीएल) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभालती हैं। गोयल ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन,



स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, आईटी, परिवहन, संपत्ति कर, यातायात और पार्क जैसे विभाग संभालें। उन्होंने अपशिष्ट वाहन निगरानी को कंप्यूटरीकृत करने, स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने और एनएमसी को पहली बार संपत्ति कर लक्ष्य हासिल करने में मदद करने जैसी पहल का नेतृत्व किया। गोयल को प्री-प्राइमरी छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने, नए पार्क विकसित करने और एनएमसी की प्रणाली के

डिजिटलीकरण का नेतृत्व करने का भी श्रेय दिया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस अधिकारी अंकित को जिला परिषद, छत्रपति संभाजी नगर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। अधिकारी मीनल करणवाल और कवली मेघना को क्रमशः जलगांव और नांदेड़ के जिला परिषदों के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। आईएएस अधिकारी करिश्मा नायर को अतिरिक्त नगर आयुक्त, नासिक नगर निगम और रंजीत मोहन यादव को परियोजना अधिकारी, आईटीडीपी, गढ़चिरोली और सहायक कलेक्टर, गढ़चिरोली सब डिवीजन, गढ़चिरोली के पद पर तैनात किया गया है।

बीएमसी ने फुटपाथों से अनधिकृत फेरीवालों को हटाने के लिए अभियान शुरू किया है

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि फेरीवालों और विक्रेताओं के अलावा, अधिकारियों द्वारा अनधिकृत संरचनाओं और झुगियों को भी हटाया जा रहा है। मुंबई के फुटपाथों को पैदल चलने वालों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के प्रयास में, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने मंगलवार को फुटपाथों पर अपनी दुकानें लगाने वाले अनधिकृत फेरीवालों और विक्रेताओं के खिलाफ एक आक्रामक अभियान शुरू किया। नागरिक अधिकारियों ने कहा कि फेरीवालों और विक्रेताओं के अलावा, अधिकारियों द्वारा अनधिकृत संरचनाओं और झोपड़ियों



को भी हटाया जा रहा है। 'मंगलवार को, अधिकारियों द्वारा फुटपाथ से अनधिकृत संरचनाओं और अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था ताकि इसे पैदल चलने वालों के लिए अनुकूल बनाया जा सके। प्रारंभ में, अभियान एफ/नॉर्थ

(माटुंगा, सायन और वडाला) में शुरू किया गया था और राज्य के शेष वार्डों में भी इसे बढ़ाया जाएगा,' संस्था ने कहा। नागरिक अधिकारियों ने कहा कि उक्त अभियान नागरिक निकाय की पैदल यात्री मुक्त पहल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, जिसके लिए बीएमसी ने नागरिक बजट में 100 करोड़ रुपये का फंड रखा था। पैदल यात्री मार्गों को खाली कराने का अभियान चरण-दर-चरण प्रक्रिया है; पहले अतिक्रमण हटाया जा रहा है और अगले चरण में लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सभी मौजूदा फुटपाथों को चौड़ा किया जाएगा।

नवी मुंबई: एनएमएमसी ने नेरुल में अनधिकृत 3-मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया

नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी) ने नेरुल के सेक्टर 8 में एक अनधिकृत जी+3 आरसीसी संरचना को ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि मालिक अवैध निर्माण के संबंध में महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन (एमआर एंड टीपी) अधिनियम के तहत जारी पूर्व नोटिस का पालन करने में विफल रहा। अतिक्रमण विभाग ने एमआर एंड टीपी अधिनियम, 1966 की धारा 54 के तहत 10 मार्च, 2025 को नोटिस दिए जाने के बावजूद, आनंद शेलार द्वारा अवैध रूप से बनाई जा रही संरचना के खिलाफ कार्रवाई की। अतिक्रमण विभाग के कर्मचारियों, 10 मजदूरों, 2 गैस कटर, 2 ब्रेकर और 4 स्लेजहैमर के साथ-साथ सुरक्षा कर्मियों और एक पुलिस दस्ते की सहायता से सहायक आयुक्त जयंत जावड़ेकर और जूनियर इंजीनियर संजय सोनटक्के की देखरेख में तोड़फोड़ की गई। एनएमएमसी ने शहरी नियोजन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शहर भर में अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

ठाकरे के तीन पूर्व नगरसेवक शिवसेना में शामिल (शिंदे)

शिव सेना के पतन के बाद, ठाकरे समूह से शिव सेना (शिंदे) में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है।

मंगलवार को भी मुंबई के तीन पूर्व नगरसेवक शिवसेना (शिंदे) में शामिल हो गए। शिंदे की शिवसेना में ठाकरे गुट से शामिल होने वालों की संख्या बढ़ रही है। शिंदे की शिवसेना आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों के लिए मुंबई के सभी वार्डों में पर्याप्त उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रही है। जनवरी में, वर्सावा निर्वाचन क्षेत्र से राजुल पटेल शिंदे की पार्टी से



निकलकर ठाकरे के पास चले गए। पंद्रह दिन पहले, शिवसेना (ठाकरे) के उप-विभागीय प्रमुख जितेंद्र जनावले भी शिवसेना (शिंदे) में शामिल हुए थे। इसके बाद रविवार को पूर्व नगरसेवक राजू पेडणेकर,

पूर्व नगरसेवक और उपविभागीय प्रमुख संजय पवार ने ठाकरे का साथ छोड़ दिया। कुर्ला के पूर्व नगरसेवक डॉ. अनुराधा पेडनेकर भी शामिल हुईं शिवसेना (शिंदे)। इस बीच, मंगलवार को तीन और पूर्व

नगरसेवक शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए। दापोली के पूर्व विधायक संजय कदम, छत्रपति संभाजी नगर के पूर्व विधायक भाऊसाहेब पाटिल चिकटगांवकर, मुंबई के तीन पूर्व नगरसेवक, पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता शिवसेना में शामिल हुए। मुंबई के भांडुप से पूर्व नगरसेवक उमेश पाटिल, चेंबूर से पूर्व नगरसेवक अंजलि नाइक और गोरेगांव से पूर्व नगरसेवक लोचना चव्हाण सहित कई पदाधिकारी, शाखा प्रमुख, उप-शाखा प्रमुख और शिव सैनिक शिव सेना (शिंदे) में शामिल हुए।